



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 4 अप्रैल, 2005 / 14 चैत्र, 1927

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, शिमला

अधिसूचना

शिमला-171 002, 1 अप्रैल, 2005

संख्या एच०पी०इ०आर०सी०/419.—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181 के साथ पठित धारा 46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सशक्त करने वाली अन्य

42-राजपत्र/2005-4-4-2005-1,624.

(199)

मूल्य : 1 रुपया।

972
चल
प्रकर
र)

सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्व प्रकाशन के उपरान्त, हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, एतद्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः :—

विनियम

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.**—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत प्रदाय पर व्यय की वसूली) विनियम, 2005 है।

(2) ये विनियम हिमाचल प्रदेश राज्य में सभी वितरण अनुज्ञापिधारियों को अपने-अपने अनुज्ञप्त क्षेत्रों में लागू होंगे।

(3) ये विनियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**—इन विनियमनों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा उपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;

(ख) "आवेदक" से परिसर का स्वामी या अधिभोगी, जो वितरण अनुज्ञापिधारी को विद्युत प्रदाय के लिए आवेदन करता है, अभिप्रेत है;

(ग) "आयोग" से हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है;

(घ) "अति उच्च विभव (EHT)" से 33000 वोल्ट से अधिक वोल्टा पर विद्युत प्रदाय, अभिप्रेत है;

(ङ) "उच्च विभव (HT)" से 650 वोल्ट से अधिक और 33000 वोल्टा से अनाधिक वोल्टा पर विद्युत प्रदाय, अभिप्रेत है;

(च) "न्यून विभव (LT)" से 650 वोल्ट और उस से कम की वोल्टा पर विद्युत प्रदाय, अभिप्रेत है;

(छ) "मास" से कलेंडर मास अभिप्रेत है तथा बिलों के प्रयोजन के लिए दो क्रमवर्ती मीटर रीडिंग में आने वाली लगभग 30 दिन की अवधि एक मास समझी जायेगी; तथा

(ज) उन सभी शब्दों और पदों के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु यहाँ परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो कि उन के लिए अधिनियम में नियत किए गए हैं।

3. न्यून विभव विद्युत प्रदाय हेतु विनिर्दिष्ट उपबन्ध.—(1) न्यून विभव विद्युत प्रदाय के लिए निम्नलिखित उपबन्ध लागू होंगे:—

(क) न्यून विभव विद्युत प्रदाय हेतु उन आवेदनों की दशा में, जहां विद्युत प्रदाय करने के लिए विद्यमान वितरण मुख्य तार से उपभोक्ता परिसर तक सिर्फ सेवा लाइन बिछाना अपेक्षित है, वितरण अनुज्ञप्तिधारी सेवा लाइन की लागत तथा उपभोक्ता के परिसर पर अन्त्य तथा मीटरिंग व्यवस्था की लागत प्राक्कलित और वसूल करेगा। इस लागत में मीटर का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा;

(ख) उन आवेदनों की दशा में, जहां न्यून विभव संयोजन हेतु आवेदक को विद्युत प्रदाय करने के लिए नया विद्युत संयंत्र, जैसे कि स्विचगियर इत्यादि, सहित वितरण ट्रांसफार्मर (डी.टी.आर.) लगाने की आवश्यकता है, वहाँ अनुज्ञप्तिधारी निम्न प्रकार से विद्युत संयंत्र की लागत प्राक्कलित और वसूल करेगा :—

वितरण ट्रांसफार्मर लगाने के संकर्म की लागत

(जिसमें स्विचगियर तथा ट्रांसफार्मर की

लागत भी है) (रुपयों में)

= P

विद्युत ट्रांसफार्मर की निर्धारित क्षमता (के.वी.ए)

= Q

प्रति के.वी.ए. लागत (रुपयों में)

= P/Q

आवेदक की संवेदित मांग

= K

विद्युत संयंत्र के लिए आवेदक द्वारा देय राशि (रुपयों में) = $K*(P/Q)$:

परन्तु यह कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी विद्युत संयंत्र तथा संकर्म की लागत वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नवीनतम प्रकाशित मन्जूर लागत आंकड़ों के आधार पर प्राक्कलित करेगा :

परन्तु यह और कि आवेदक की संवेदित मांग पूरी करने के लिए प्रस्तावित वितरण ट्रांसफार्मर (डी.टी.आर.) का न्यूनतम आकारमान व्यक्तिशः इकहरे चरण (फेज) के लिए 6.3 के.वी.ए., 10 के.वी.ए. 16 के.वी.ए. का अथवा अधिकोषण प्रक्रिया या तीन चरण (फेज) के लिए 25 के.वी.ए. का होगा :

परन्तु यह और कि यदि प्रदाय अथवा अतिरिक्त प्रदाय के लिए, और पश्चात्पूर्वी आवेदन प्राप्त होते हैं, और विद्यमान विद्युत संयंत्र में—

- (i) अतिरिक्त प्रदाय करने के लिए फालतू पर्याप्त क्षमता है; या
- (ii) फालतू क्षमता है, परन्तु अतिरिक्त प्रदाय की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, और अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए विद्यमान संयंत्र को मजबूत करने अथवा उसमें आवर्धन करने की आवश्यकता है;

तो अनुज्ञप्तिधारी अतिरिक्त प्रदाय पूरा करने की लागत उसी रीति से, प्राक्कलित करेगा तथा उक्त लागत, जिसमें उपगत व्यय भी सम्मिलित है, 8 प्रतिशत वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज सहित यथानुपात के आधार पर वसूल करेगा और पुराने/विद्यमान विद्युत संयंत्र, जो कि आवर्धन के कारण फालतू हो गए हों, की अवक्षणि लागत का प्रत्यय प्राक्कलन में दिया जाएगा;

- (ग) उन आवेदनों की दशा में, जहां आवेदक को विद्युत प्रदाय हेतु वितरण ट्रांसफार्मर लगाने और 11 के.वी., 22 के.वी. या न्यून विभव लाइन बिछाने, मजबूत करने, आवर्धित करने अथवा विस्तारित करने की आवश्यकता है, तो वितरण विज्ञप्तिधारी ऐसे 11 के.वी., 22 के.वी. या न्यून विभव लाइन के अनुभाग की लागत वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यथा प्रकाशित नवीनतम मंजूर लागत आंकड़ों पर आधारित, प्रति किलोमीटर के आधार पर प्राक्कलित तथा वसूल करेगा ।

(2) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (अनुरोध पर अनुज्ञप्तिधारी का विद्युत प्रदाय करने का कर्तव्य) विनियम, 2004 में यथाविनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर विद्युत प्रदाय करेगा ।

(3) उस दशा में जहां अपेक्षित भार 25 के.वी.ए. से अधिक है, तो आवेदक, यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपेक्षा की गई है, अपने परिसर में ट्रांसफार्मर तथा सहयुक्त उपस्कर, जिसमें मीटरिंग व्यवस्था भी आती है, के लिए आवश्यक स्थान उपलब्ध करेगा।

4. उच्च विभव विद्युत प्रदाय हेतु विनिर्दिष्ट उपबन्ध.—(1) उच्च विभव प्रदाय के लिए निम्नलिखित उपबन्ध लागू होंगे:—

(क) नये संयोजन के लिए आवेदनों की दशा में, जहां आपूर्ति के लिए विद्यमान तन्त्र से उपभोक्ता परिसर तक उच्च विभव लाइन का सिर्फ विस्तारण अपेक्षित है तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी संकर्म, सेवा लाइन तथा उपभोक्ता परिसर में अन्त्य एवं मीटरिंग व्यवस्था की लागत (जिसमें मीटर की लागत, मीटरिंग के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त विद्युत-प्रेषण-ट्रांसफार्मर तथा/अथवा अन्तःस्थित ट्रांसफार्मर की लागत नहीं है) प्राक्कलित और वसूल करेगा। वितरण अनुज्ञप्तिधारी, वितरण सेवा लाइन की प्रति किलोमीटर की दर से तथा मीटरिंग व्यवस्था की लागत अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यथा नवीनतम प्रकाशित मन्जूर लागत के आकड़ों के आधार पर प्राक्कलित तथा वसूल करेगा;

(ख) उन आवेदनों की दशा में जहां आवेदक को विद्युत प्रदाय करने के लिए नया विद्युत ट्रांसफार्मर लगाना या 33/11 के.वी. उप-केन्द्र में, बे-एक्सटेंशन (Bay-Extension) सहित या उसके बिना विद्यमान विद्युत ट्रांसफार्मर की क्षमता आवर्धित करना आवश्यक है, वहां वितरण अनुज्ञप्तिधारी, विनियम 3 के उप-विनियम (1) में यथावर्णित रीति से अवेष्टित संकर्मों की लागत प्राक्कलित तथा वसूल करेगा;

(ग) उन आवेदनों की दशा में जहां किसी एकमात्र आवेदक को विद्युत प्रदाय करने के लिए नया 33/11 के.वी. उप-केन्द्र स्थापित करना आवश्यक है, वितरण अनुज्ञप्तिधारी ऐसे उप-केन्द्र की लागत प्राक्कलित तथा वसूल करेगा;

(घ) उन आवेदनों की दशा में जहां आवेदक को विद्युत प्रदाय करने के लिए विद्युत ट्रांसफार्मर तथा/अथवा 33/11 के.वी. उप-केन्द्र स्थापित करने के लिए उच्च विभव लाइन बिछाने, मजबूत करने, आवर्धित करने या विस्तारित करने की

आवश्यकता है, वहां वितरण अनुज्ञप्तिधारी ऐसी अति उच्च विभव लाइन के अनुभाग की प्रति किलोमीटर के आधार पर लागत प्राक्कलित तथा वसूल करेगा:

परन्तु यह कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी विद्युत संयंत्र तथा संकर्मों की लागत अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नवीनतम प्रकाशित मन्जूर लागत आंकड़ों के आधार पर प्राक्कलित करेगा :

परन्तु यह और कि यदि प्रदाय अथवा अतिरिक्त प्रदाय के लिए, और पश्चात्पूर्वी आवेदन प्राप्त होते हैं, और विद्यमान विद्युत संयंत्र में—

(i) अतिरिक्त प्रदाय करने के लिए फालतू पर्याप्त क्षमता है; या :

(ii) फालतू क्षमता है, परन्तु अतिरिक्त प्रदाय की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, और अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए विद्यमान संयंत्र को मजबूत करने अथवा उसमें आवर्धन करने की आवश्यकता है;

तो अनुज्ञप्तिधारी अतिरिक्त प्रदाय पूरा करने की लागत उसी रीति से, प्राक्कलित करेगा तथा उक्त लागत, जिसमें उपगत व्यय भी सम्मिलित है, 8 प्रतिशत वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज सहित यथानुपात के आधार पर वसूल करेगा और पुराने/विद्यमान विद्युत संयंत्र, जो कि आवर्धन के कारण फालतू हो गए हों, की अवक्षणि लागत का प्रत्यय प्राक्कलन में दिया जाएगा;

(2) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, हिमाचल प्रदेश विनियामक आयोग (अनुरोध पर अनुज्ञप्तिधारी का विद्युत प्रदाय करने का कर्तव्य) विनियम, 2004 में यथाविनिर्दिष्ट कालावधि में विद्युत प्रदत्त करेगा ।

(3) यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपेक्षा की गई है, आवेदक अपने परिसर में ट्रांसफार्मर तथा सहयुक्त उपस्कर, जिसमें मीटरिंग व्यवस्था भी आती है, के लिए आवश्यक स्थान उपलब्ध करेगा ।

5. अति उच्च विभव विद्युत प्रदाय हेतु विनिर्दिष्ट उपबन्ध.—(1) अति उच्च विभव विद्युत प्रदाय हेतु निम्नलिखित उपबन्ध लागू होंगे:—

- (क) नये संयोजन के लिए आवेदनों की दशा में, जहां विद्युत प्रदाय करने के लिये विद्यमान पारेषण उप-केन्द्र से उपभोक्ता परिसर तक अति उच्च विभव लाइन का सिर्फ विस्तारण अपेक्षित है, तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी उक्त लाइन तथा उपभोक्ता परिसर में अन्त्य एवं मीटरिंग व्यवस्था की लागत (जिसमें मीटर की लागत मीटरिंग के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त विद्युत-प्रेषण ट्रांसफार्मर तथा/अथवा अन्तःशक्ति ट्रांसफार्मर की लागत नहीं है) प्राक्कलित करेगा। वितरण अनुज्ञप्तिधारी लाइन की प्रति किलोमीटर की दर से लागत तथा मीटरिंग व्यवस्था की लागत, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यथा नवीनतम प्रकाशित मन्जूर लागत के आंकड़ों के आधार पर प्राक्कलित और वसूल करेगा;
- (ख) उन आवेदनों की दशा में जहां आवेदक को विद्युत प्रदाय करने के लिए नया विद्युत ट्रांसफार्मर लगाना अथवा पारेषण उप-केन्द्र में, अति उच्च विभव उप-केन्द्र पर बे-एक्सटेंशन (Bay-Extension) सहित या उसके बिना, विद्यमान विद्युत ट्रांसफार्मर की क्षमता आवर्धित करना आवश्यक है, अनुज्ञप्तिधारी विनियम 3 के उप-विनियम (1) के खण्ड (ख) में यथा वर्णित रीति से संकर्मों की लागत प्राक्कलित तथा वसूल करेगा;
- (ग) उन आवेदनों की दशा में जहां आवेदक को विद्युत प्रदाय करने के लिए विद्युत ट्रांसफार्मर स्थापित करने के लिए अति उच्च विभव लाइन बिछाने, मजबूत करने, आवर्धित करने या विस्तारित करने की आवश्यकता है, वितरण अनुज्ञप्तिधारी ऐसी अति उच्च विभव लाइन के अनुभाग की प्रति किलोमीटर के आधार पर लागत प्राक्कलित तथा वसूल करेगा :

परन्तु यह कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी वितरण अथवा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नवीनतम प्रकाशित मन्जूर लागत आंकड़ों के आधार पर, विद्युत संयंत्र तथा संकर्मों की लागत प्राक्कलित करेगा :

परन्तु यह और कि यदि प्रदाय अथवा अतिरिक्त प्रदाय के लिए, और पश्चात्पूर्वी आवेदन प्राप्त होते हैं, और विद्यमान विद्युत संयंत्र में—

- (i) अतिरिक्त प्रदाय करने के लिए फालतू पर्याप्त क्षमता है; या

- (ii) फालतू क्षमता है, परन्तु अतिरिक्त प्रदाय की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, और अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए विद्यमान संयंत्र को मजबूत करने अथवा उसमें आवर्धन करने की आवश्यकता है;

तो अनुज्ञप्तिधारी अतिरिक्त प्रदाय पूरा करने की लागत उसी रीति से, प्राक्कालित करेगा तथा उक्त लागत, जिसमें उपगत व्यय भी सम्मिलित है, 8 प्रतिशत वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज सहित यथानुपात, के आधार पर वसूल करेगा और पुराने/विद्यमान विद्युत संयंत्र, जो कि आवर्धन के कारण फालतू हो गए हों, की अवक्षणि लागत का प्रत्यय प्राक्कलन में दिया जाएगा;

(2) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, हिमाचल प्रदेश विनियामक आयोग (अनुरोध पर अनुज्ञप्तिधारी का विद्युत प्रदाय करने का कर्तव्य) विनियम, 2004 में यथाविनिर्दिष्ट कालावधि में विद्युत प्रदत्त करेगा।

(3) यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपेक्षा की गई है, आवेदक अपने परिसर में ट्रांसफार्मर तथा सहयुक्त उपस्कर, जिसमें मीटरिंग व्यवस्था भी आती है, के लिए आवश्यक स्थान उपलब्ध करेगा।

6. लागत वसूली.—(1) उप-विनियम (2) के अध्याधीन रहते हुए, आवेदक द्वारा विनियम 3 के उप-विनियम (1), विनियम 4 तथा विनियम 5 के अंतर्गत देय राशि काटने के उपरान्त, विद्युत संयंत्र तथा/अथवा विद्युत लाइन की अतिशेष लागत का या तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विनिधान किया जायेगा या आवेदक द्वारा संदाय किया जायेगा और जहां अनुज्ञप्तिधारी की विनिधान मन्जूरी में यह लागत अनुज्ञात नहीं है वहां अनुज्ञप्तिधारी कुल अतिशेष लागत आवेदक से वसूल करेगा :

परन्तु यह कि जब कभी भी संयंत्र से तथा/अथवा विद्युत लाइन से नये संयोजन दिये जाते हैं तब यह लागत 8 प्रतिशत वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज सहित यथानुपात के आधार पर आवेदक को लौटाई जाएगी :

परन्तु यह और कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट कोई बात अन्यथा होते हुए भी, देय राशि पश्चात्तर्वर्ती आवेदकों से वसूलीय होगी तथा जब तक राशि पूर्णतया संदत्त नहीं

हो जाती है उपभोक्ता, जिसने प्रथमतः अतिशेष लागत का भुगतान किया हो, के बिलों में चिन्ह द्वारा लगातार निरपवाद रूप में वसूलीय दर्शायी जाएगी ।

(2) अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत प्रदाय प्रारम्भ करने के तीन मास से भीतर आवेदक/उपभोक्ता को प्रारम्भिक अनुमानित राशि के सम्बन्ध में आधिक्य अथवा कमी दर्शाते हुए, यथासम्भव, मदवार आकड़ों में अन्तर सहित, विषय-क्रम में अनुमानित तथा वास्तविक व्यय का ब्योरा देते हुए व्यय लेखा देगा तथा यदि आवेदक को अतिरिक्त सूचना अपेक्षित हो, तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी उसे, अध्यपेक्षा की प्राप्ति से दस दिन के भीतर, उपलब्ध करेगा :

परन्तु यह कि जहां इस उप-विनियम के अधीन वास्तविक व्यय—

(क) प्रारम्भिक अनुमानित लागत से, तीन प्रतिशत से अधिक, कम है, वहाँ अनुज्ञप्तिधारी अधिक राशि को व्यय लेखा देने से 30 दिनों के भीतर लौटाएगा; अथवा

(ख) प्रारम्भिक अनुमानित लागत से तीन प्रतिशत से अधिक है, वहाँ आवेदक अनुमानित लागत तथा वास्तविक व्यय का अन्तर केवल 3 प्रतिशत तक ही संदत्त करेगा और अतिशेष राशि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा धारित की जाएगी ।

(3) इन विनियमों में कोई बात अन्यथा होते हुए भी, विद्युत संयंत्र और/या विद्युत लाइन पर केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार अथवा किसी अन्य अभिकरण से प्राप्त अनुदान या आर्थिक सहायता से उपगत व्यय वसूलीय नहीं होगा ।

(4) उस दशा में जब अनुमानित लागत का संदाय करने के पश्चात् और—

(क) संकर्म को पूरा करने से पूर्व यदि आवेदक विद्युत लेने से इन्कार कर देता है, तो उपगत किया गया वास्तविक युक्तियुक्त व्यय काट कर निक्षिप्त राशि तीस दिन के भीतर लौटाई जाएगी; या

(ख) नए संयोजन के लिए आवेदक को विद्युत प्रदाय करने हेतु विद्युत लाइन बिछाने, संयंत्र निर्मित करने तथा अन्य सुविधाएं देने से पूर्व यदि आवेदक विद्युत लेने से इन्कार कर देता है तो अनुज्ञप्तिधारी आवेदक को तीस दिन के भीतर पूरी अनुमानित राशि लौटाएगा ।

7. **मार्ग-गमानाधिकार सहमति तथा अधिग्रहण.**—अधिनियम की धारा 67 (2) तथा 180 (2) (ख) के अधीन, राज्य सरकार द्वारा बनाए नियमों के अधीन रहते हुए, आवेदक को संयोजन उपलब्ध करते हुए, अनुज्ञप्तिधारी के संकर्मों में समुचित समन्वय रखने हेतु विद्युत पारेषण तथा वितरण अथवा तार संचार या दूरभाषण के लिए अपेक्षित तारें, खम्बे, दीवारगीर ब्रैक्टेस, रोधन यन्त्र एवं सांघित्र लगाने के लिए अनुज्ञप्तिधारी, आवेदक के खर्च पर, मार्ग-गमानाधिकार सहमति प्राप्त करने तथा अधिग्रहण करने का प्रयास करेगा :

परन्तु यह कि जहां दूसरों की भूमि, परिसर तथा मकान के ऊपर से तारें डाली जानी हों, तो तारें, यथासाध्य, उक्त भूमि या परिसर की सीमादीवाल, अथवा मकान के सैट-बैक (Set Back), गलियों तथा सड़कों के ऊपर से निकाली जाएंगी ।

8. **भुगतान.**—मांग सूचना प्राप्त होने पर आवेदक संकर्म शुरू करने से पूर्व विनियम 3 के उप-विनियम (1), विनियम 4, विनियम 5 तथा विनियम 7 के अधीन देय शतप्रतिशत राशि जमा करेगा ।

9. **मासिक माटक राशि द्वारा भुगतान करने का विकल्प.**—(1) उस दशा में जब विद्युत प्रदाय के संकर्म, अनुज्ञप्तिधारी की मन्जूर विनिधान योजना में सम्मिलित हैं; आवेदक को विकल्प होगा कि चाहे वह विनियम 3 के उप-विनियम (1), विनियम 4 तथा 5 में यथाविनिर्दिष्ट संकर्म अथवा सेवा लाइन (जिसमें अन्त्य एवं मीटरिंग व्यवस्था भी है), विद्युत संयंत्र तथा/अथवा 11 के.वी., 22 के.वी. निम्न विभव उच्च विभव और अति उच्च विभव लाईन की लागत का एक मुश्त भुगतान करे या 8% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज सहित वास्तविक विद्युत प्रदाय की तारीख से दस वर्ष की अवधि के भीतर बराबर मासिक किश्तों में भुगतान करे ।

(2) उस दशा में, जब कोई उपभोक्ता जो पहले मासिक किश्तों में भुगतान करने का विकल्प करता है और बाद में एक मुश्त भुगतान करना चाहता है, उसे कुल लागत में से उस द्वारा संदत्त की जा चुकी किश्तों की राशि काट कर (डिसकौन्टिड कैश फ्लो) की 8% की दर पर वर्तमान शुद्ध मूल्य का भुगतान करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा । उन सभी मामलों में उस तारीख से जब उपभोक्ता कुल लागत का भुगतान कर देता है, मासिक किश्तें लेना बन्द हो जाएगा ।

10. **संकर्म का अनुरक्षण.**—(1) अनुज्ञप्तिधारी तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में

अन्तर्विष्ट कोई बात अन्यथा होते हुए भी, किसी आवेदक की अध्यपेक्षा के अनुसरण में विद्युत प्रदाय हेतु निर्मित सभी संकर्मों या उसके किसी भाग, जिसके लिए अध्यपेक्षा करने वाले आवेदक ने भुगतान कर दिया हो, को अनुरक्षित करेगा और अनुज्ञप्तिधारी को उक्त संकर्मों से किसी अन्य भागी आवेदक को विद्युत प्रदाय करने का अधिकार होगा और वे संकर्म वितरण अनुज्ञप्तिधारी की सम्पत्ति हो जाएंगे ।

(2) अनुज्ञप्तिधारी तथा उपभोक्ता/आवेदक मीटर उपस्कर अथवा मीटर उपस्कर को आलम्ब देने वाले स्विचगियर के बीच का अंतरापृष्ठ दायित्व होगा ।

11. अस्थायी विद्युत प्रदाय.—इन विनियमों में कोई भी बात अन्यथा होते हुए भी, परन्तु प्रारम्भिक प्रतिभूति निक्षेप का पूर्व भुगतान करने पर, अस्थायी प्रदाय हेतु सेवा लाइन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बिछाई जाएंगी तथा वास्तविक व्यय, जिस में सामग्री मूल्य, मजदूरी तथा विभागीय प्रभार भी हैं, आवेदक द्वारा धारित किया जायेगा :

परन्तु यह कि इस विनियम के अधीन वसूलीय राशि में से लौटाई गई सामग्री का मूल्य, उस की दशा को ध्यान में रखते हुए, घटाया जाएगा :

परन्तु यह और कि यदि अनुज्ञप्तिधारी, आवेदक द्वारा उसको देय बकाया को समायोजित करने के उपरान्त, आवेदक को तीस दिन के भीतर लौटा देता है, तो आवेदक को ब्याज संदत नहीं किया जाएगा ।

12. विभागीय प्रभार.—आवेदक इन विनियमों के अधीन वसूलीय व्यय के साथ-साथ उसे विद्युत प्रदाय के लिए, संकर्मों की अनुमानित लागत का 11 प्रतिशत की दर पर, विभागीय प्रभार का संदाय करेगा ।

स्पष्टीकरण.—इन विनियमों के प्रयोजन हेतु "विभागीय प्रभार" में स्थापना प्रभार, औजार व संयंत्र प्रभार, संपरीक्षा व लेखा प्रभार, निर्माण के दौरान अनुरक्षण, स्टॉक तथा डिजाइन क्षति प्रभार तथा मुख्यालय अनुपाततः व्यय सम्मिलित होंगे ।

13. मानक लागत आंकड़े.—(1) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, वार्षिक आधार पर प्रति वर्ष 31 दिसम्बर तक, आयोग की मन्जूरी के लिए लागत आंकड़ा पुस्तिका (जिसमें विभागीय प्रभार भी

होंगे) प्रस्तुत करेगा और मन्जूर लागत आंकड़ा पुस्तिका को वर्ष की 1 अप्रैल तक प्रकाशित करेगा। यह आवेदक को विद्युत प्रदाय करने के लिए विद्युत लाइन बिछाने तथा/अथवा संकर्मों और/अथवा विद्युत संयंत्र के बनाने के लिए प्रारंभिक प्राक्कलन तैयार करने का आधार होगी :

(2) वितरण अनुज्ञप्तिधारी मांगने पर हितबद्ध व्यक्तियों को, युक्तियुक्त भुगतान पर, लागत आंकड़ा पुस्तिका की प्रतियां उपलब्ध करेगा ।

14. मांग सूचना.—आवेदक को, हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (अनुरोध पर अनुज्ञप्तिधारी का विद्युत प्रदाय करने का कर्तव्य) विनियम, 2004 में अधिकथित समय सीमा के भीतर, इन विनियमों के साथ साथ अन्य विनियमों की शर्तें अनुबद्ध करते हुए 90 दिन तक की विधिमान्य मांग सूचना रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा दी जाएगी ।

15. संक्रमणकालीन उपबन्ध.—जब तक विनियम 13 के अनुसार लागत आंकड़ा पुस्तिका प्रकाशित नहीं की जाती है, या इन विनियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से छः मास की अवधि व्यतीत नहीं हो जाती है, जो भी पहले हो, तब तक अनुज्ञप्तिधारी की नवीनतम मन्जूर स्कीमों के लिए 33 के.वी. तथा इसके नीचे के संकर्मों के बारे में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा वर्ष के लिए प्रकाशित लागत आंकड़े तथा 33 के.वी. से अधिक के संकर्मों के बारे में विद्युत वित्त निगम द्वारा प्रयुक्त आंकड़े प्रयोग में लाए जाएंगे ।

16. कठिनाइयां दूर करना.—(1) यदि इन विनियमों को प्रभाव देने में कोई कठिनाई आती है तो आयोग, स्वतः अथवा इसे आवेदन करने पर, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, ऐसी समुचित कार्रवाई करने के लिए अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को ऐसे समुचित कार्रवाई करने के लिए, जो अधिनियम से असंगत नहीं है और उसे ऐसी कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक या समीचीन प्रतीत होती है, निर्दिष्ट कर सकता है ।

(2) इस विनियम के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, उसके दिए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा ।

17. निर्वचन.—इन विनियमों के सम्बन्ध में उद्भूत सभी विवादक, आयोग द्वारा अवधारित किए जाएंगे तथा उन विवादकों पर आयोग का निर्णय अन्तिम होगा ।

18. आदेश व दिशा-निर्देश जारी करना.—अधिनियम तथा इन विनियमों के अध्यक्षीन रहते हुए, आयोग उन मामलों में, जिनके लिए ये विनियम आयोग को निदेश देने के लिए सशक्त करते हैं, समय-समय पर, विनियमों के अनुपालन में तथा विभिन्न विषयों में प्रक्रिया अपनाने हेतु एवं प्रासंगिक या आनुषंगिक विषयों पर आदेश तथा पद्धति निदेश दे सकेगा ।

आयोग के आदेश द्वारा
हस्ता/-
सचिव ।

(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT)

HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 1st April, 2005

No. HPERC/419.—In exercise of the powers conferred by section 46 read with section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, after previous publication, makes the following regulations, namely :—

REGULATIONS

1. **Short title, extent and commencement.**—(1) These regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Recovery of Expenditure for Supply of Electricity) Regulations, 2005.

(2) These regulations shall be applicable to all distribution licensees in their respective licensed areas, in the State of Himachal Pradesh.

(3) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Definitions.—In these Regulations, unless the context otherwise requires,—

- (a) “Act” means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);
- (b) “applicant” means the owner or occupier of any premises who makes an application to the distribution licensee for supply of electricity;
- (c) “Commission” means the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission;
- (d) “extra high tension (EHT)” means supply voltages above 33000 volts;
- (e) “high tension (HT)” means supply voltages more than 650 volts and upto and inclusive of 33000 volts;
- (f) “low tension (LT)” means supply voltages of 650 volts and below;
- (g) “month” means the calendar month and the period of about 30 days between the two consecutive meter readings shall also be regarded as a month for purpose of billing; and
- (h) other words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act shall have the meanings as assigned to them in the Act.

3. Specific provision for low tension supply.—(1) The following provisions shall apply for low tension supply,—

- (a) in the case of application for low tension supply where such supply requires only laying the service line from the existing distributing mains to the consumer's premises, the distribution licensee shall estimate and recover the cost of service line and the cost of terminal and metering arrangements at the premises of the consumer. The cost of meter shall not be included;
- (b) in the case of application where there is a need to erect new electrical plant such as distribution transformer (DTR) alongwith the switch gear etc., for extending supply to the applicant for low tension connection, the licensee shall estimate and recover the cost of electrical plant as follows,—

Cost of the works of erection of distribution transformer
(DTR) including the cost of switch-gear
and transformer (in rupees)

=P

Rated capacity of DTR (kVA)	=Q
Cost per kVA (in rupees)	=P/Q
Contract Demand of the applicant (kVA)	=K
Amount payable by the applicant towards electrical plant (in rupees)	=K*(P/Q):

Provided that the distribution licensee shall estimate the cost of electrical plant and works based upon the approved latest cost data as published by the distribution licensee:

Provided further that the standard minimum size of the distribution transformer (DTR) viz. single phase 6.3 kVA, 10 kVA, 16 kVA individually or in banking mode or three phase 25 kVA shall be proposed to meet with the contract demand of the applicant:

Provided further that in case there are subsequent applications for supply or additional supply and the existing electrical plant has—

- (i) adequate spare capacity to meet with the additional demand, or
- (ii) spare capacity but not sufficient to meet with the additional demand, and there is need to strengthen/augment the existing electrical plant for meeting the additional supply,

the licensee shall estimate and/or recover the cost in the like manner, including the actual cost already incurred, with compound interest at the rate of 8% per annum on prorata basis and the credit of the depreciated cost of old/existing electric plant rendered surplus on account of augmentation shall be afforded in the estimate;

- (c) in the case of applications where there is need to erect, strengthen, augment or extend the 11 kV, 22 kV or LT line in order to establish a distribution transformer and extend supply to the applicant, the distribution licensee shall estimate and recover the cost of such section of 11 kV, 22 kV or LT line per kilometre basis based upon the approved latest cost data as published by the distribution licensee.

(2) The distribution licensee shall provide the supply within the time frame as specified in Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Licensee's Duty for Supply of Electricity on Request) Regulations, 2004.

(3) Where the requisitioned load exceeds 25 kVA the applicant shall provide the required space within applicant's premises for transformer and associated equipments including metering arrangements, if so required by the licensee.

4. Specific provisions for high tension supply.—(1) The following provisions shall apply for the high tension supply,—

- (a) in the case of the application for new connection, where such supply requires only extension of high tension line from the existing network to the consumer's premises, the distribution licensee shall estimate and recover the cost of works, service line and the cost of terminal and metering arrangements at the premises of the consumer, but not including the cost of meter and current transformers and/or potential transformer used for metering. The distribution licensee shall estimate and recover the cost of service line on per kilometre basis and the cost of metering arrangements based on the latest approved cost data as published by the distribution licensee;
- (b) in the case of application where there is a need to erect a new power transformer or augment the capacity of existing power transformer with or without bay extension at a 33/11 kV sub-station for extending supply to the applicant, the distribution licensee shall estimate and recover the cost of the works involved in the *manner* mentioned in clause (b) of sub-regulation (1) of regulation 3;
- (c) in the case of applications where there is a need to erect a new 33/11 kV sub-station in order to extend supply to an individual applicant, the distributing licensee shall estimate and recover the cost of such sub-station.
- (d) in the case of application where there is need to erect, strengthen, augment or extend the HT line in order to establish a power transformer and/or 33/11 kV sub-station for extending supply to the applicant, the distribution licensee shall estimate and recover the cost of such section of EHT line on per kilometre basis:

Provided that the distribution licensee shall estimate the cost of electrical plant and works based upon the approved latest cost data as published by the distribution licensee:

Provided further that in case there are subsequent applications for supply or additional supply and the existing electrical plant has—

- (i) adequate spare capacity to meet with the additional demand, or
- (ii) spare capacity but not sufficient to meet with the additional demand, and there is need to strengthen/augment the existing electrical plant for meeting the additional supply,

the licensee shall estimate and/or recover the cost in the like manner, including the actual cost already incurred, with compound interest at the rate of 8% per annum on prorata basis and the credit of the depreciated cost of old/existing electric plant rendered surplus on account of augmentation shall be afforded in the estimate.

(2) The distribution licensee shall provide the supply within the time frame as specified in Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Licensee's Duty for Supply of Electricity on Request) Regulations, 2004.

(3) The applicant shall provide the required space within applicant's premises for transformer and associated equipments including metering arrangements, if so required by the licensee.

5. Specific provision for extra high tension supply.—(1) The following provisions shall apply for extra high tension supply,—

- (a) In case of application for new connection, where such supply requires only extension of extra high tension line from the existing transmission substation to the consumer's premises, the distribution licensee shall estimate and recover the cost of such line and the cost of terminal and metering arrangements at the premises of the consumer, but not including the cost of meter and current transformer and/or potential transformer used for metering. The distribution licensee shall estimate and recover the cost of line on per kilometer basis and the cost of metering arrangements based on the latest cost data as published by the transmission licensee;
- (b) in case of application where it is required to erect a new power transformer or augment the capacity of existing power transformer with or without bay extension at a EHT substation, for extending supply to the applicant, the licensee shall estimate and recover the cost of the works in the manner mentioned in clause (b) of sub-regulation (1) of regulation 3.
- (c) in case of application where there is need to erect, strengthen, augment or extend the EHT line in order to establish a power transformer for extending supply to the applicant, the distribution licensee shall estimate and recover the cost of such section of EHT line on per kilometre basis:

Provided that the distribution licensee shall estimate the cost of electrical plant and works based upon the approved latest cost data as published

by the distribution or the transmission licensee:

Provided further that in case there are subsequent applications for supply or additional supply and the existing electrical plant has—

- (i) adequate spare capacity to meet with the additional demand, or
- (ii) spare capacity but not sufficient to meet with the additional demand, and there is need to strengthen/augment the existing electrical plant for meeting the additional supply,

the licensee shall estimate and/or recover the cost in the like manner, including the actual cost already incurred, with compound interest at the rate of 8% per annum on prorata basis and the credit of the depreciated cost of old/existing electric plant rendered surplus on account of augmentation shall be afforded in the estimate.

(2) The distribution licensee shall provide the supply within the time frame as specified in Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Licensee's Duty for Supply of Electricity on Request) Regulations, 2004.

(3) The applicant shall provide the required space within applicant's premises for transformer and associated equipments including metering arrangements, if so required by the licensee.

6. Recovery of cost.—(1) Subject to the provisions of sub-regulation (2), the balance cost of electrical plant and/or electric line after deducting the amount payable by the applicant under sub-regulation (1) of regulation 3, regulation 4 and regulation 5 shall be either invested by the licensee or paid for by the applicant and where licensee's investment approval does not permit this cost, the licensee shall recover the total balance cost from the applicant:

Provided that the balance cost shall be refunded to the applicant as and when new connections are installed or given from the electrical plant and/or electrical line on prorata basis with the interest rate of 8% compounded annually:

Provided further that notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, balance cost due shall be recoverable from subsequent applicant(s) and the bills of the consumer who had paid the balance cost shall be invariably flagged continuously until paid fully.

(2) The licensee shall render to the applicant/consumer the account of expenditure showing the excess or deficit in relation to initial estimated amount within three months after

release of connection giving details of itemwise estimation and actual expenditure along with the item wise figures of variance to the extent possible and, if applicant requires any additional information, the distribution licensee shall furnish the same within ten days of receipt of such requisition:

Provided that where the actual expenditure,—

- (a) is less than the initial estimated cost by more than 3% the licensee shall refund the excess amount, within 30 days from the date of submission of the account, or
- (b) exceeds the initial estimated cost by more than 3%, the applicant shall pay the difference between the initial estimated cost and the actual expenditure to the extent of 3% only and any amount in excess of 3% shall be borne by the licensee.

(3) Notwithstanding anything to the contrary contained in these regulations the expenditure on the electrical plant and/or electric lines incurred from any grant or subvention from the Central or State Government or any other agency shall not be recoverable.

(4) Where, after the payment of the estimated cost and,—

- (a) before the completion of work, if the applicant declines to take the supply, the amount paid by him shall be refunded within thirty days, after deducting there from, the actual reasonable expenditure incurred; or
- (b) before starting the work of laying of electric line, erection of electrical plant and creating any other facilities for extending supply to the applicant seeking new connection, if applicant declines to take the supply, total amount of estimate shall be refunded by the licensee to the applicant within thirty days.

7. Way leaves, Consents and Acquisitions.—Subject to the provisions of rules framed by the State Government under section 67(2) and 180(2) (b) of the Act, the licensee shall, at the cost of applicant, try to obtain any wayleaves, consents and acquisitions required for placing of any wires, poles, wall brackets, stays apparatus and appliances for the transmission and distribution of electricity, or for the transmission of telegraphic or telephonic communications necessary for proper coordination of the works of the licensee while giving connection to the applicant:

Provided that where wires are to pass over other person's land, premises or building, the wires shall be routed along the boundary lines of the said land, set-back of the building, streets and roads which ever is feasible.

8. Manner of Payments.—The applicant shall, before the commencement of work, deposit 100% payment on notice of demand for amount payable under sub-regulation (1) of regulation 3, regulation 4, regulation 5 and regulation 7.

9. Option of paying through monthly rentals.—(1) Where the works for supply are covered under the approved investment plan of the licensee, the applicant shall have the option either to pay the cost of works and/or service line (including terminal and metering arrangement), electrical plant and/or 11 kV, 22 kV or LT line in lumpsum as specified under sub-regulations (1) of regulation 3, regulations 4, 5 and 7 or pay the same alongwith interest @ 8%, compounded annually, in equal monthly installments within a period of 10 years reckoned from the actual date of supply of electricity.

(2) Where a consumer who in the first instance elects to pay the monthly installments, afterwards desires to pay in lumpsum shall be allowed to pay the balance amount of the total cost after adjusting the installments already paid by him on Net Present Value @ 8% Discounted Cash Flow. The monthly installments shall cease from the date, the entire cost is so paid by the consumer in all cases.

10. Maintenance of works.—(1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, all the works erected for providing supply in pursuance of requisition by the applicant or any portion of which may have been paid for by the applicant making requisition shall be maintained by the licensee and the licensee shall also have the right to supply electricity to any other prospective applicant through the said works and the said works shall become the property of the distribution licensee.

(2) The interface liability between the licensee and the consumer/applicant shall be metering equipment or the switchgear supporting the metering equipment.

11. Temporary Supplies.—Notwithstanding anything to the contrary contained in these regulations, but subject to the prior payment of initial security deposit, in the case of temporary supplies, the service lines shall be laid by the Licensee and the actual cost including the cost of material, labour and departmental charges shall be borne by the applicant :

Provided that the cost of the material returned shall, after taking into consideration its condition, be reduced from the cost recoverable under this regulation:

Provided further that where the licensee refunds, after making adjustment of the outstanding amount due to him by the applicant, within a period of thirty days no interest shall be paid to the applicant.

12. Departmental Charges.—In addition to the expenditure recoverable under these regulations, the applicant shall have to pay the departmental charges for the supply of electricity to him at the rate of 11% of the estimated cost of works.

Explanation.—For the purposes of this regulation, the expression “departmental charges” shall include establishment charges, tools and plant charges, audit and accounts charges, maintenance during construction, loss on stock and design charges and head office prorata expense.

13. Standard cost data.—(1) The distribution licensee shall on an annual basis submit to the Commission by 31 December of each year a cost data (including departmental charges) book for approval and publish the approved cost data book by 1st April of the year, which shall be the basis of making the initial estimate for erection of electric line and/or any other works and/or electrical plant in order to provide supply to the applicant.

(2) The distribution licensee shall make available the copies of the cost data book to any interested person on demand at a reasonable charge.

14. Demand Notice.—Demand notice valid for 90 days stipulating all the conditions of these regulations as well as of other regulations shall be sent by the registered A.D post to the applicant with in the time frame laid down in Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Licensee's Duty for Supply of Electricity on Request) Regulations, 2004.

15. Transitional Provision.—Cost data published for the year by the Rural Electrification Corporation in respect of works of 33 kV and below and used by Power Finance Corporation in respect of works above 33 kV in latest sanctioned scheme of the licensee shall be used until the cost data book is published in accordance with the regulation 13 or a period of six months from the date of these regulations coming into force, whichever is earlier.

16. Power to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these Regulations, the Commission may *suo motu* or an application by general or special order take suitable action, or direct the distribution licensee to take such suitable action, not being inconsistent with the Act, which appears to be necessary or expedient for the purpose of removing such difficulties.

(2) Every order made under this regulation shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislative Assembly.

17. Interpretation.—All issues arising in relation to interpretation of these regulations shall be determined by the Commission and the decision of the Commission on such issues shall be final.

18. Issue of orders and practice directions.—Subject to the provisions of the Act and these regulations, the Commission may, from time to time, issue orders and practice directions in regard to the implementation of this regulation and procedure to be followed on various matters, which the Commission has been empowered by this regulation to direct and matters incidental or ancillary thereto.

BY ORDER OF THE COMMISSION,

Sd/-
Secretary

